Vol 7, Issue 8, 2024 **Impact Factor: 5. 355** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2024.7.8.7616

IJAMSR

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का लघु उद्यमियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: एक समीक्षा

Simmi Gahlot
Research Scholar, Kalyan PG College, Bhilai Nagar, Chhattisgarh

Dr. Nidhi Monika Sharma
Assistant Professor, Bhilai Mahila Mahavidyalay, Chhattisgarh

Dr. Ravish Kumar Soni
Assistant Professor, Kalyan PG College, Bhilai Nagar, Chhattisgarh

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने लघु उद्यमियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है, जिससे नवोदित उद्यमियों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आई है। महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला है, जिससे महिला सशक्तिकरण में सहायता मिली है। इसके अलावा, स्थानीय और कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारत में लघु उद्यमियों के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू या विस्तारित कर सकें। शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। यह योजना वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

प्रमुख शब्द : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम (MSME) , गारंटी-मुक्त ऋण

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

I. परिचय

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता उन छोटे उद्यमियों को प्रदान की जाती है जो माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में लगे होते हैं। यह योजना निवेशकों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है, ताकि उनके वित्तीय विकास को समर्थन किया जा सके। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण की भी प्रावधानिकता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और संसाधनों से लैस हो सकें। ऐसा करके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है और छोटे उद्यमों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाती है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)[*] की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015[†] को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन लघु उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपने छोटे व्यवसायों को शुरू करना या विस्तारित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत, गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। मुद्रा का अर्थ "माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी" है, और इस योजना के माध्यम से उधारकर्ताओं को तीन श्रेणियों में ऋण दिया जाता है: शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक), और तरुण (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक)।

1.1 उद्देश्य और महत्त्व

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है

i. वित्तीय समावेशन: इस योजना का लक्ष्य उन लोगों तक पहुंचना है जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर हैं और जिन्हें बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
ii. रोजगार सृजन: लघु और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान कर नए रोजगार के अवसर पैदा करना।
iii. महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
iv. आर्थिक विकास: लघु उद्यमियों[‡] के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना।

1,2 योजना की संरचना

मुद्रा योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लघु उद्यमियों को निम्नलिखित ऋण उत्पाद प्रदान किए जाते हैं

i. शिशु: यह ऋण उन नवोदित उद्यमियों को दिया जाता है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
ii. किशोर: इस श्रेणी में उन उद्यमियों को शामिल किया जाता है जो अपने व्यवसाय को स्थापित कर चुके हैं और उसे विस्तारित करना चाहते हैं। इसमें 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
iii. तरुण: इस श्रेणी में उन उद्यमियों को शामिल किया जाता है जो अपने स्थापित व्यवसाय को और अधिक विस्तार देना चाहते हैं। इसमें 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

[*] शाहिद, महम्मद, और महम्मद इरशाद। "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर एक वर्णनात्मक अध्ययन।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, विशेष अंक (2016): 121-125।
[†] रामंजनेयालु, एन., और आर. श्रीनिवास। "सूक्ष्म और लघु उद्यमिता को बढ़ावा देने में मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की समीक्षा - महिला उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता के विशेष संदर्भ के साथ।"
[‡] पांडे, रमेश, आदि। सामान्य अध्ययन पेपर 1 2020 (हिंदी)। पियर्सन एजुकेशन इंडिया, 2019।

IJAMSR
International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

1.3 योजना का प्रभाव

PMMY ने लघु उद्यमियों[§] के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निम्नलिखित बिंदुओं पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:

i. वित्तीय समावेशन में वृद्धि: इस योजना के तहत कई नवोदित उद्यमियों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है।
ii. रोजगार के अवसर: लघु उद्यमों के विकास से नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आई है।
iii. महिला उद्यमिता: इस योजना के तहत महिलाओं को भी प्रमुखता से ऋण प्रदान किया गया है, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।[**]
iv. स्थानीय उद्योगों का विकास: लघु और कुटीर उद्योगों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिला है।

II. साहित्य की समीक्षा

दुबे, पी. के. बी., और चावले, वी. जी. (2024)। सूक्ष्म उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हालांकि कई को अपनी ज़रूरत के हिसाब से वित्तीय सहायता पाने में संघर्ष करना पड़ता है। छोटी फ़र्मों और उद्यमियों को इस बाधा को दूर करने में मदद करने के प्रयास में, सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। लेकिन PMMY की प्रभावशीलता इसकी सेवाओं की पहुँच और जागरूकता पर निर्भर करती है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य मुंबई क्षेत्र के नागरिकों के PMMY के बारे में ज्ञान और पहुँच का मूल्यांकन करना है। व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए, यह शोध एक मिश्रित-विधि रणनीति का उपयोग करता है जो मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों को एकीकृत करता है। संख्यात्मक आँकड़ों के अलावा, सर्वेक्षण आवेदन प्रक्रिया से गुजरने, आवश्यक विवरण प्राप्त करने और कार्यक्रम के लाभों का लाभ उठाने में संभावित प्राप्तकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को आगे बढ़ाने में PMMY की प्रभावकारिता के बारे में हितधारकों के दृष्टिकोण के बारे में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। यह शोध नीति निर्माताओं को मुंबई में पीएमएमवाई के बारे में जागरूकता और पहुंच में सुधार करने में मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे लक्षित रणनीतियां बन सकती हैं जो पहुंच को बढ़ाती हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती हैं और उद्यमिता के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ी कार्यान्वयन चुनौतियों और अवसरों में अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि प्रदान करके भारत में वित्तीय समावेशन और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर बढ़ते ज्ञान और चल रही चर्चा में योगदान देंगे। यह जागरूकता-पहुंच के अंतर को पाटने और उद्यमिता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर पीएमएमवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में अनुरूप हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालता है।

[§] अरविंदराज, के., और जय गणेश बाला। "दक्षिण भारत में पीएमएमवाई का प्रदर्शन विश्लेषण।" आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट 20.1 (2018): 24-28।
[**] वानखेडे, and सुश्री. कल्पना मो. "वतर्मान संदर्भ में खादी की प्रासंगिकता एवं महिलांए." (2015).

I J A M S R
International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

खान, एच., हुसैन, एफ., और मजहर, एस.एस. (2024) अध्ययन मुद्रा योजना के लिए महिला उद्यमियों की प्राथमिकताओं की जांच करता है, जो महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों का समर्थन करने वाली एक सरकारी योजना है। विश्लेषण मुद्रा योजना जागरूकता और अपने व्यवसायों में महिला उद्यमियों की स्थिति के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए क्रॉस टेबुलेशन और चिस्क्वेयर टेस्ट जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करता है। परिणाम सांख्यिकीय महत्व के साथ महिला उद्यमियों के बीच मुद्रा योजना के लिए प्राथमिकता का संकेत देते हैं। हालाँकि अध्ययन में स्व-रिपोर्ट किए गए डेटा और क्रॉस-सेक्शनल डिज़ाइन पर निर्भरता जैसी सीमाएँ हैं, लेकिन यह सरकारी योजनाओं के लिए महिला उद्यमियों की प्राथमिकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऐसी योजनाओं की समझ और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए, ज्ञान के आदान-प्रदान और हितधारक भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष मुद्रा योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हैं, जो नीति निर्माण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पहलों में योगदान दे सकता है। आगे के शोध से क्षेत्र-विशिष्ट प्राथमिकताओं और महिला उद्यमियों के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण पर मुद्रा योजना के दीर्घकालिक प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, साथ ही उद्यमिता में उभरती चुनौतियों और अवसरों को संबोधित किया जा सकता है।

साहू, वी. के., बराल, एस. के., और सिंह, आर. (2024)। विकास पर वर्तमान चर्चा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर देती है। इस अध्ययन का उद्देश्य समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए आर्थिक न्याय कार्यक्रमों और स्थायी दृष्टिकोणों के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन करते हुए स्वदेशी महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का पता लगाना है। इस संदर्भ में, शोध का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए गए वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रमों के कई पहलुओं का पता लगाना है। इसका लक्ष्य आर्थिक समानता और दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने पर चल रही चर्चा में योगदान देना है। इस जांच का उद्देश्य वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रियाओं की जांच करना और स्वदेशी महिलाओं को आर्थिक न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाने की संभावना को उजागर करना है। ऐसा करके, यह इन समुदायों के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जो अधिक समतावादी और लचीला हो। भारत के विकास संबंधी विमर्श की पृष्ठभूमि में, यह अध्ययन आदिवासी महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण के अनिवार्य क्षेत्र में गहराई से उतरता है। आर्थिक न्याय पहलों और समावेशी विकास की ओर संधारणीय मार्गों के बीच जटिल संबंधों को उजागर करने पर केंद्रित, हमारे शोध का उद्देश्य स्वदेशी महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। हमारी जांच विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के लिए तैयार किए गए वित्तीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों के सूक्ष्म परिदृश्य पर केंद्रित है, जो आर्थिक समानता और स्थायी सामाजिक परिवर्तन पर चल रही बातचीत में महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश कर रही है। वित्तीय समावेशन प्रक्रियाओं की जटिलताओं को नेविगेट करके, हमारी जांच एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहाँ स्वदेशी महिलाएँ न केवल आर्थिक न्याय प्राप्त करती हैं, बल्कि एक अधिक न्यायसंगत और लचीले समाज को फिर से आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। यह पहचाना गया है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, शैक्षिक संभावनाओं का विस्तार करने, आय के अंतर को कम करने, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और पूर्वाग्रही सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का मुकाबला करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, लक्षित हस्तक्षेपों में माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम, गाँव की बचत और ऋण, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और सरकारी योजनाएँ शामिल हैं। सरकारी, गैर-सरकारी और सामुदायिक हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि एक अधिक समतावादी समाज बनाया जा सके जो आदिवासी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाता है।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

मिश्रा, एस. (2023) दक्षिण एशिया में स्थित भारत, भूमि क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर सातवें स्थान पर है और 1.2 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जबकि पर्याप्त जनसंख्या देश के भीतर एक विशाल संभावित बाजार को दर्शाती है, यह समवर्ती रूप से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण रोजगार चुनौतियों को जन्म देती है। हाल के दिनों में, कॉलेज के छात्रों के बीच स्वरोजगार जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे वे माता-पिता के समर्थन, शैक्षणिक संस्थानों या पारंपरिक अवसरों की प्रतीक्षा करने पर कम निर्भर हो गए हैं। इसके बजाय, ये छात्र सक्रिय रूप से अपने लिए नई संभावनाओं की तलाश करते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य सरकार की पहल, मुद्रा योजना की जांच करना है, जिसे स्टार्ट-अप को वित्तीय रूप से समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे बेरोजगारी के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में उद्यमशीलता को सशक्त बनाया जा सके। शोधपत्र का उद्देश्य उद्यमिता के विकास पर PMMY (MUDRA) के प्रभाव का अध्ययन करना है, विशेष रूप से महिलाओं जैसे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के बीच। पाटिल, ए.एस. (2024) भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र (NCSBS) है। अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र में हैं। एनसीएसबीएस किसी देश के आर्थिक विस्तार की आधारशिला हैं, लेकिन गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपंजीकृत व्यवसायों के रूप में चलता है। वे कानूनी रूप से कराधान के अधीन नहीं हैं और सटीक खाता बही नहीं रखते हैं। इसलिए बैंकों के लिए उन्हें ऋण देना चुनौतीपूर्ण है। इस उद्योग के अधिकांश हिस्से के पास बाहरी वित्तपोषण स्रोतों तक पहुँच नहीं है। बैंक इस उद्योग को बहुत कम सहायता प्रदान करते हैं; 15% से भी कम बैंक ऋण एमएसएमई या सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को दिया जाता है। इस योजना का फोकस 'अनफंडेड को फंड' देना है। यह निबंध पीएमएमवाई और इसके महत्व, मुद्रा बैंक के उत्पादों और योजनाओं, योजना के विकास की वर्तमान स्थिति और महाराष्ट्र में पीएमएमवाई के लाभों को समझने का प्रयास करता है।

देसाई, एन., और थिमैया, एन. (2023) अप्रैल 2015 में, भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) योजना की स्थापना की। यह शोध पत्र इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। MUDRA योजना देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूक्ष्म उद्यमों और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। अध्ययन आर्थिक सिद्धांतों, अनुभवजन्य डेटा और नीति विश्लेषण का उपयोग करके प्रवृत्तियों, पैटर्न और योजना के प्रदर्शन की जांच करता है। MUDRA योजना के ढांचे, लक्ष्यों और कार्यान्वयन की जांच की जाती है। अध्ययन में इंडिया स्टेट, सरकारी वेबसाइटों और विद्वानों की पत्रिकाओं से विश्वसनीय माध्यमिक डेटा का उपयोग किया गया है। MUDRA योजना का शिशु, किशोर और तरुण पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश लगातार ऋण खातों में सबसे आगे है, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र स्वीकृत और वितरित राशियों में सबसे आगे हैं। आर्थिक गतिविधियाँ क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती हैं, जिसमें दक्षिणी राज्य अधिक भाग लेते हैं। यह योजना के प्रशिक्षण और रोजगार परिणामों की भी जांच करता है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सफलता दर्शाता है। राजनेता, अर्थशास्त्री और हितधारक इस शोध से मुद्रा योजना की ताकत और कमजोरियों के बारे में जान सकते हैं। इस शोध का उद्देश्य मुद्रा योजना को अनुकूलित और बेहतर बनाना है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसकी जटिलताओं और प्रभाव की जांच करके राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों को बेहतर ढंग से हासिल किया जा सके।

कुमार, सी.एस., और दिव्याथेजोमूर्ति, वी. (2024)। स्वतंत्र भारत में अभी भी आदिवासियों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता की कमी के कारण आदिवासी पिछड़े हालात में जी रहे हैं। आदिवासियों के पास ज़मीन नहीं है, इसलिए वे वित्तीय ज़रूरतों के लिए मुख्यधारा के समाज से संपर्क नहीं कर सकते हैं और सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करती है। बहुत से आदिवासी लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं और आज भी यनाडी जनजातियाँ अपने घर या उचित नौकरी के अवसरों

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

के बिना खानाबदोश जीवन जी रही हैं। ये योजनाएँ यनाडी आदिवासियों के लिए एक आदर्श जीवन जीने और शिक्षा, नौकरी और रोज़गार के अवसरों का हिस्सा बनने के लिए बहुत उपयोगी हैं। हालाँकि ये कार्यक्रम अच्छे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम सभी आदिवासियों की स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हैं। समय के साथ-साथ भारतीय सरकार की प्राथमिकताएँ भी बदली हैं। आज़ादी के बाद पहले सरकार ने कृषि पर ध्यान केंद्रित किया, फिर औद्योगीकरण, बाद में बिजली क्षेत्र, अब हम डिजिटलीकरण के युग में हैं। इसी तरह, आदिवासियों की ज़रूरतें और अपेक्षाएँ समय-समय पर बदल रही हैं।

मिंज एट अल., (2022) एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है क्योंकि यह रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करता है। हालांकि, इन उद्योगों के लिए सबसे बड़ी बाधा मुख्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय पहुंच की कमी है। बाधा को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने भारत में सूक्ष्म उद्यमियों को दिए गए ऋणों के लिए ऋणदाता को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA) की स्थापना की। इस पत्र का उद्देश्य स्थापना के बाद से कम सुविधा प्राप्त उद्यमी समूहों ((महिलाएं, नए उद्यमी, अल्पसंख्यक और अन्य)) के लिए खोले गए खातों की कुल संख्या, स्वीकृत राशि और वितरित की गई राशि के संदर्भ में मुद्रा के समग्र प्रदर्शन को उजागर करना है। अध्ययन मुद्रा डेटाबेस की वार्षिक रिपोर्टों से एकत्र माध्यमिक डेटा पर आधारित है। खोले गए खातों की कुल संख्या और वितरित राशि का उपयोग करके वार्षिक विकास और सीएजीआर की गणना की गई थी। गेम-हॉवेल पोस्ट-हॉक विश्लेषण के साथ वन-वे एनोवा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या कम सुविधा प्राप्त उद्यमी समूहों के बीच वितरित ऋण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। अध्ययन से पता चलता है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान मुद्रा ऋण में पर्याप्त प्रगति हुई। अध्ययन यह समझने में सहायता करेगा कि मुद्रा कम सुविधा प्राप्त उद्यमियों के सशक्तीकरण में कैसे सहायता करती है।

III. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारतीय सरकार की एक प्रमुख पहल है जो छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना उन उद्यमियों को लक्षित करती है जो माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम में लगे होते हैं, और उन्हें वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस योजना के माध्यम से, उद्यमियों को बिना किसी संपत्ति या ऋण के संबंधित वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने का मौका मिलता है। यह योजना ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। इसके अलावा, यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है और स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है, जिससे नौकरी के लिए न केवल उत्पादन, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ती है। इसके माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

आर्थिक सहायता: छोटे उद्यमियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता का मुख्य लक्ष्य छोटे उद्यमियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। यह योजना छोटे उद्यमियों को ऋण की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे अपने व्यापार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बिना किसी संपत्ति के गारंटी के, वित्तीय संस्थाओं से छोटे उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। इससे उनके व्यवसाय में वृद्धि होती है, उत्पादकता बढ़ती है और वे नए उत्पादों का निर्माण करने के लिए तकनीकी उन्नति कर सकते हैं। यह छोटे उद्यमियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें अपने व्यवसाय को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहुंच प्रदान करता है।[††]

[††] भाजपा, भोपाल. "चरैवेति अक्टूबर अंक 2022." (2022).

वित्तीय संसाधन: गारंटी के बिना उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय संसाधनों का प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें बिना किसी गारंटी के छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना उन उद्यमियों को लक्षित करती है जो सामान्य बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संपत्ति या कागजात नहीं होती। इस योजना के माध्यम से, यहां कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, जो व्यावसायिक लोगों को ऋण प्राप्त करने में सहायक बनाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, उद्यमियों को तीन प्रमुख श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है: 'शिशु', 'किशोर', और 'तरुण'। 'शिशु' श्रेणी में, लोन राशि 50,000 रुपये तक होती है, 'किशोर' श्रेणी में यह राशि 50,000 से 5 लाख रुपये तक होती है, और 'तरुण' श्रेणी में ऋण राशि 5 लाख से 10 लाख रुपये तक होती है। ऋण की लागत, ब्याज दर और वित्तीय संस्था के नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस योजना के माध्यम से, छोटे उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों की सरल और उचित प्राप्ति की सुविधा मिलती है। उन्हें बिना किसी भय के अपने व्यवसाय के लिए पूंजी प्राप्त करने का मौका मिलता है, जिससे वे अपने विचारों को अमल में लाने के लिए सक्षम होते हैं। इससे उनके व्यापार की वृद्धि होती है, जो उनके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मदद करती है, साथ ही रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाती है। इस रूप में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है।

उद्यमिता विकास: प्रशिक्षण और उद्यमिता के विकास कार्यक्रमों की प्रावधानिकता

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों के उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और उद्यमिता के विकास कार्यक्रमों की प्रावधानिकता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, उद्यमियों को व्यवसायिक कौशलों, प्रबंधन तकनीकों, विपणन और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसके अलावा, वे बाजार की मांग और प्रौद्योगिकी के आधार पर अपने व्यवसाय को अद्यतित रखने के लिए नवाचारी विचारों का भी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। ये कार्यक्रम उद्यमियों को स्वतंत्र और सकारात्मक सोच का विकास करने में मदद करते हैं और उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों से लैस करते हैं।

रोजगार सृजन: छोटे व्यवसायों के विस्तार से नौकरियों की उत्पत्ति

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान करना है, जो छोटे व्यवसायों के विस्तार से नौकरियों की उत्पत्ति को बढ़ावा देता है। यह योजना व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करती है और साथ ही नौकरी की मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विस्तारित करने की संभावनाएं प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप, छोटे उद्यमों में वृद्धि होती है, जिससे वे अधिक नौकरियों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये उद्यमी अक्सर अपने व्यापार की वृद्धि के साथ-साथ अपने कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करते हैं ताकि वे अपनी उत्पादन की वृद्धि हेतु अधिक जिम्मेदारी संभाल सकें। छोटे उद्यमों का विस्तार सीधे नौकरियों के सृजन में सक्रिय भूमिका निभाता है। जब एक व्यवसाय अपनी गतिविधियों को विस्तारित करता है, तो उसकी वृद्धि के साथ-साथ नई नौकरियों की भी उत्पत्ति होती है। ये नौकरियाँ अक्सर स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां नौकरी के अवसरों की कमी होती है। इसके अलावा, ये नौकरियाँ सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, क्योंकि वे आर्थिक रूप से पिछड़े और निराधार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। छोटे उद्यमों के व्यापार का विस्तार उनकी पूंजी और संसाधनों की वृद्धि के साथ होता है, जो उन्हें अधिक नौकरियों की उत्पत्ति करने में सक्षम बनाता है। वे अक्सर अपने व्यवसाय के साथ-साथ अपने कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करते हैं, जो उनकी व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक होती है।

Vol 7, Issue 8, 2024 **Impact Factor: 5. 355** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2024.7.8.7616

IJAMSR

International Journal of
Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

आत्मनिर्भरता: स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करना और स्व-सहायता के माध्यम से अपने जीवन को संचालित करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।[‡‡] योजना के माध्यम से, छोटे उद्यमियों को स्व-रोजगार के लिए उत्साहित किया जाता है। उन्हें अपने विचारों को अमल में लाने और अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। यह उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव कराता है और उनकी सामर्थ्य को मजबूत करता है। स्व-रोजगार के अवसर उन्हें न केवल आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारते हैं। इस योजना के माध्यम से, उद्यमिता को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है। यह छोटे उद्यमों को समर्थ बनाता है और उन्हें व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से आवश्यक संसाधनों की पहुंच प्रदान करता है। यह योजना उन्हें नए विचारों को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उनके व्यवसाय में नवाचार और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इससे उन्हें अधिक आत्म-विश्वास और सकारात्मक सोच की प्राप्ति होती है, जो उन्हें व्यवसाय के संचालन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से, उद्यमिता को समर्थ बनाने के लिए उचित गाइडेंस और प्रशिक्षण की प्रावधानिकता होती है। छोटे उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे और उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलता है।

IV. निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लघु उद्यमियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम से नवोदित और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित और विस्तारित कर सके हैं। यह योजना न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हो रही है। मुद्रा योजना का सतत् और प्रभावी क्रियान्वयन भारत के लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा और आर्थिक विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा।

संदर्भ

1. मिंज, डब्ल्यू.पी., भौमिक, जी., और कुशारी, एस. "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उद्यमिता विकास: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण." 2022.
2. मिश्रा, एस. "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का प्रभाव अध्ययन." 2023.
3. पाटिल, ए.एस. "महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति का अध्ययन." 2024.
4. दुबे, पी.के.बी., और चावले, वी.जी. "मुंबई क्षेत्र के निवासियों के बीच प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के बारे में जागरूकता और पहुंच के स्तर का आकलन." 2024.
5. खान, एच., हुसैन, एफ., और मजहर, एस.एस. "मुद्रा योजना के लिए महिला उद्यमियों की प्राथमिकताओं की खोज: एक सांख्यिकीय विश्लेषण." 2024.
6. साहू, वी.के., बराल, एस.के., और सिंह, आर. "आदिवासी महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण: सतत आर्थिक न्याय पहल और समावेशी विकास की दिशा में मार्गों की जांच." *एशियन जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अकाउंटिंग,* 24(4), 182-194.
7. देसाई, एन., और थिमैया, एन. "भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की गतिशीलता का विश्लेषण." 2023.
8. कुमार, सी.एस., और दिव्याथेजोमूर्ति, वी. "भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में यानाडी जनजाति की स्थिरता पर सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रभाव." *ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एनवायर्नमेंटल इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट (ईसीईएम),* 11(1), 42-49.
9. सिंह, एन.आर. "समावेशी और विकसित भारत 2047: बेहतर भविष्य के लिए एक सक्रिय रणनीति." *शैक्षिक प्रशासन: सिद्धांत और व्यवहार,* 30(5), 9116-9122.
10. पाटिल, ए.एस. "भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई का योगदान." 2024.

[‡‡] वानखेडे, and सुश्री. कल्पना मो. "वतर्मान संदर्भ में खादी की प्रासंगिकता एवं महिलांए." (2015).